झूठ, फरेब तथा दमन-उत्पीड़न के नौ साल

केन्द्र की संप्रग सरकार ने इस मई में अपने लगातार नौ साल पूरे किये। इस पर कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाया। पर क्या वास्तव में जश्न मनाने लायक कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार के पास कुछ है? या यदि वे जश्न मना रहे हैं तो उन्हें किस बात का जश्न मनाना चाहिए?

कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार को इस बात का जश्न मनाना चाहिये कि इसने झूठ-फरेब से शासन करने तथा अपनी सरकार को बनाये रखने में हर किसी को मात दे दी है। केवल उदाहरण लें। देश में गरीब कितने हैं और कितने ग़रीबों को सरकारी राहत दी जानी चाहिए, इस मामले में इस सरकार की बातें अब गहरे शोध का विषय बन गई हैं।

कांग्रेस की सरकार पिछले नौ सालों में लगातार ही अल्पमत की सरकार रही है। यह कई सहयोगियों पर टिकी रही है। इनमें से कुछ तो परले दरजे के सौदेबाज रहे हैं। तब भी सरकार कैसे टिकी रही? केवल इसी तरह कि कांग्रेस गिरहकटों के मुकाबले पूरी डकैत निकली। इसने बहुत आसानी के साथ सौदेबाज चाहे तृणमूल कांग्रेस के रहे हों, डीएमके या फिर सपा-बसपा के। लेकिन झूठ-फरेब ही संप्रग शासन का मूल तत्व नहीं रहा है। मज़दूर

एनटोनी, मनमोहन, चिदंबरम, सोनिया : लूट जारी रखने की जुगत में

वर्ग आर मेहनतकश जनता के संबंध में दमन चौतरफ़ा रहा है। यह मज़दूरों का रहा है तो किसानों का भी, आदिवासियों का रहा है तो राष्ट्रीयताओं का भी। और इसमें कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार ने किसी शर्म-लिहाज का परिचय नहीं दिया है। उपरोक्त सब इस कदर हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी केवल अपने विरोधियों की नालायकी पर ही भरोसा कर रही है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए सरकार कांग्रेस पार्टी के पास क्या था? कुछ नहीं। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी जीत गई, क्योंकि उसकी विरोधी भाजपा उससे भी ज़्यादा निकम्मी थी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के नौ साल पूरे होने पर अपने भाषण में यह कहा कि यदि उनकी पार्टी को अगले साल फिर सरकार बनाने का मौका मिला तो वे देश की आर्थिक वृद्धि दर को फिर आठ प्रतिशत पर ले आयेंगे, लेकिन अभी ऐसा हो भी जाता है तो इससे किसे फायदा होगा? 2004 से 2008 तक जो आठ-साढ़े आठ प्रतिशत विकास दर रही उसका किसे फायदा हुआ। क्या देश की मज़दूर- मेहनतकश आबादी की आय और सम्पत्ति आठ-साढ़े आठ प्रतिशत विकास दर रही उसका किसे फयदा हुआ? क्या देश की मज़दूर-मेहनतकश आबादी की आय और सम्पत्ति आठ-साढ़े आठ प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ी? क्या यह सच्चाई नहीं है कि ज़्यादातर मज़दूरों-मेहनतकश की आय और सम्पत्ति बढ़ने के बदले घटी है? तो फिर वह बढ़ती कहां गई? मनमोहन सिंह और उनके लगुए-भगुए इसका जवाब नहीं देंगे। यह सारी बढ़ती पूंजीपतियों की तिजोरी में गई है जिसके कारण उनकी पूंजी बेतहाशा बढ़ी है।

वास्तव में मनमोहन सिंह यह बात कहकर पूंजीपति वर्ग को आश्वस्त कर रहे हैं कि संप्रग के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर उनके दिन अच्छे रहेंगे। वे किसी तरह भारत की गिरती विकास दर को वापस ले आयेंगे और पूंजीपतियों की पूंजी उसी तेज गति से बढ़ने लगेगी। मनमोहन सिंह को नरेन्द्र मोदी से डर भी लग रहा होगा जो भारतीय पूंजीपतियों को यह कह कर लुभा रहे हैं कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरती विकास दर को पलट देंगे। इन वादों और दावों से अलग संप्रग सरकार भविष्य में उन बड़े-बड़े घोटालों के लिये याद की जायेगी, जिन पर इसके नेताओं ने पूरी बेशर्मी से परदा डालने की कोशिश की थी। हालांकि, वक्त के साथ यह सब इतना रोजमर्रा का मामला बन गया है कि बेहद बड़े पैमाने के घोटाले ही अब चौंका पाते हैं। कुछ सौ या हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले अब कोई मायने नहीं रखते। कांग्रेस की विरोधी पार्टी भाजपा एक कपटी बिल्ली की तरह इस ताक में बैठी है कि कब चुनाव हों और दिल्ली की गद्दी उसके हाथ में आये। वह सोच रही है कि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का वही हाल होगा जो कर्नाटक में उसका अपना हुआ। यह उम्मीद एक उतनी ही धूर्त और पतित पार्टी के लिये कोई बुरी चीज नहीं है। पर इस उम्मीद को यथार्थ में बदलने के लिये कुछ बुनियादी जरूरी चीजें भाजपा में नदारद दिख रही हैं। उनके बड़े भाई कांग्रेसी ठीक इसी बात पर 2014 में अपना खोटा सिक्का फिर चल जाने की आस लगाये बैठे हैं। संप्रग के नौ सालों का यही है हिसाब-किताब।

-नागरिक

मज़दूर आवाज

मज़दूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मज़दूर वर्ग का कार्य है

हमारा आन्दोलन जारी रहेगा

6 मई 2013 को कैथल जिले में डीसी कार्यालय के केम्पस में हमने एक सभा व महापंचायत आहूत की। इसमें दो हज़ार से ज़्यादा मज़दूर, हमारे परिवार व आस-पास के गांव-कस्बों के आम मेहनतकश लोग शामिल हुए। इसने मारुति-सुजुकी के प्रबंधन व हरियाणा सरकार दोनों को मज़दूर वर्ग पर उनके दमनकारी आक्रमण के ख़िलाफ़ कड़ा संदेश दिया और बताया कि मेहनतकश लोग ज़्यादा मजबूत एकता से लड़ेंगे और मांग उठी कि 147 जेल में बंद हमारे मज़दूर साथियों को शीघ्र रिहा किया जाए और बर्खास्त मज़दूरों को काम पर वापिस लिया जाये।

इस महापंचायत में देश के सभी क्षेत्रों से मज़दूरों के संगठनों व स्वतंत्र और केन्द्रीय यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हमारे साथ एकजूटता प्रदर्शित की। हमारे साथ एकजुटता प्रदर्शन में हीरो होण्डा एम्प्लॉईज यूनियन, आईएमटी मानेसर, रीको एम्प्लॉईज यूनियन धारूहेडा एफसीसी रिको एम्लॉइज यूनियन, आइएमटी मानेसर, सुजुकी पावर ट्रेन एम्प्लॉइज यूनियन सॉलिडेरिटी कमेटी मुम्बई, मोल्डर एण्ड स्टील वर्कर्स यूनियन, लुधियाना पंजाब, एनटीयूआई, मुम्बई, सीटू, हरियाणा, वर्कर्स आर्गेनाइजेशन और महिला-छात्र युवा तथा अन्य संगठन जैसे-इंकलाबी मज़दूर केन्द्र, भारत सभा, बिगुल मज़दूर दस्ता, इंकलाबी जन आवाज, पंजाब नौजवान, डीवाईएफआई हरियाणा, समतामूलक महिला संगठन और कई अन्य शामिल थे।

इसी महापंचायत में हमने पूरे हरियाणा राज्य के 150 पंचायत नेताओं का समर्थन व एकजुटता भी हासिल की। इसने हमारे संघर्ष को एक मजबूत सामाजिक आधार दिया और हम आशा करते हैं कि यह मेहनतकश जनता के सभी वर्गों को प्रभावित करने वाले सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों का एक हिस्सा है। कैथल में हमारे धरने का 46 वां दिन था। जो 24 मार्च 2013 को शुरू हुआ था।

इसमें 28 मार्च से शुरू हुआ आमरण अनशन भी शामिल था जिसे हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा और राज्य उद्योग मंत्री आर.एस. सुरजेवाला के आश्वासन पर 8 दिन बाद स्थायी रूप से रोक दिया। लेकिन इसने उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाला क्योंकि आज भी सरकार आम मेहनतकश लोगों व मज़दूरों की कीमत पर मारुति-सुजुकी कंपनी के हितों को पूरा कर रही है। जिनका यह प्रतिनिधित्व करती है। सरकार हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ने के लिए भारी खर्च कर रही है जबकि हमें हमारी नौकरी से बर्खास्त कर जेलों में डाल दिया है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और पुलिस द्वारा किये जाने वाले तमाम तरीकों से उत्पीड़न व प्रताड़ना का हम जिक्र नहीं कर सकते।

दिन भर चली लम्बी सभा के बाद हमने शाम को डीसी ऑफिस के सामने सड़क को जाम कर दिया क्योंकि शांतिपूर्वक संघर्ष को चलाने के बावजूद हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तब डीसी हमारे ज्ञापन को लेने व राज्य सरकार को भेजने के लिये आया। महापंचायत ने सरकार को चेतावनी दी कि हमारी दर्ज मागों को न मानने पर इससे ज़्यादा मेहनतकश लोगों की बड़ी हुयी ताकत के साथ हम 19 मई 2013 को कैथल में उद्योग मंत्री के घर का घेराव करेंगे।

हमारा संघर्ष फैक्टरी में सम्मानजनक काम व हमारे अधिकारों के लिए शुरु हुआ था। हमारी दो मुख्य मागें हैं-संगठित होने का अधिकार व अवैध ठेका प्रथा का खात्मा। इसके कारण कम्पनी ने हम पर हमला किया।

हमारा संघर्ष फैक्टरी में सम्मानजनक काम व हमारे अधिकारों के लिए शुरू हुआ था। हमारी दो मुख्य मांगें हैं-संगठित होने का अधिकार व अवैध ठेका प्रथा का खात्मा। इसके कारण कम्पनी ने हम पर हमला किया। मालिक व शासक वर्ग मज़दूरों व मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ना चाहते हैं। कम्पनी-सरकार-प्रशासन के इस तरह के गठजोड़ के ख़िलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। यह आन्दोलन अब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे नहीं मान ली जातीं।

8 मई 2013
-प्रोविजनल वर्किंग कमेटी,
मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन
-नागरिक

गुजरात प्रदेश में तथाकथित विकास और भूमि अधिग्रहण

गुजरात में तथाकथित विकास के आधार पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी आजकल प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुये हैं। इस तथाकथित विकास की बरसात में वे 2002 में गोधरा हत्याकांड की कालिख अपने चेहरे से मिटाना चाहते हैं, वहीं वे इस तथाकथित विकास के पीछे किसानों की उपजाऊ ज़मीन के बर्बर अधिग्रहण को छुपाना चाहते हैं। इन अधिग्रहणों से व्यापक रूप से फैलने वाली बेरोजगारी को तो वे संज्ञान में लेना ही नहीं चाहते।

मिथीविरदी में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2010 में 600 मेगावाट का नाभिकीय संयंत्र लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी लागत 64,000 करोड़ है। गुजरात सरकार ने उस प्लांट को लगाने की अनुमति दे दी, जिसकी वजह से 15000 लोग सीधे-सीधे प्रभावित हुये।

भूमि अधिग्रहण के क्रम में ही कच्छ के रण में मुन्द्रा में बने अदाणी ग्रुप के एक सेज (एसईजेड) को 10,000 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गयी। इसकी वजह से 56 गांव और 126 ताल्लुक विस्थापित हुये जहां के निवासी मछली मार कर अपनी रोजी-रोटी चला रहे थे। जब यह सेज बनकर तैयार हो जायेगा तो यह और भी कई गांवों को विस्थापित करेगा। अदाणी ग्रुप को यह जमीन कोड़ियों के भाव दे दी गयी। उस ज़मीन की बाज़ार कीमत जहां 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, वहीं उसे यह जमीन 1 रुपये से लेकर 32 रुपये प्रति वर्ग मी. के हिसाब से दे दी गयी। ज्ञात रहे नरेन्द्र मोदी के चुनावी खर्च उठाने वाले तथा मुख्य समर्थक औद्योगिक घरानों में अदाणी ग्रुप प्रमुख है।

इसके अलावा, महुआ में निरमा सेज के लिए सीमेंट प्लांट लगवाने के लिये 268 हेक्टेयर भूमि दे दी गयी, जिसमें लाइमस्टोन को तोड़कर सीमेंट बनाने में उसका उपयोग होगा और पास ही स्थित बन्दरगाह से उसको भेज दिया जायेगा।

इस जमीन को सेज बनाने के लिए देने के पीछे तर्क यह दिया गया कि यह बंजर भूमि है। लेकिन सच्चाई यह है कि महुआ में नासिक (महाराष्ट्र) के बाद सबसे ज़्यादा प्याज पैदा होता है। इस सेज के बनने से 15,000 लोगों का रोजगार छिन गया और इस प्लांट में काम मिला केवल 416 लोगों को, वह भी अकुशल मज़दूर के रूप में। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1980 में जमीन अधिग्रहित करनी शुरू की थी।

इस जमीन का उपयोग भूमिहीनों को जमीन देने तथा छोटे व मध्यम पैमाने के कारखानों को जमीन देना था और अगर पांच साल में वह उस जमीन को विकसित न कर सका तो वह वापस किसानों को दी जानी थी। परन्तु उस जगह में 262 इंडस्ट्रीज में से केवल 182 ही काम कर रहे हैं, जबकि बाकी जमीन का बड़ा हिस्सा देशी व विदेशी बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। इनमें रिलायंस, टाटा, एस्सार, एल एंड टी और अदाणी ग्रुप हैं। इसके अलावा गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन ग्रुपों के लिए जमीन अधिग्रहण करने का भी काम कर रहा है।

जब टाटा ने नैनो कार का प्लांट बंगाल के सिंगूर से स्थानान्तरित करने की योजना बनाई तो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने पूल में से उसे 440 हेक्टेयर जमीन दी और जब टाटा ने 960 हेक्टेयर जमीन की मांग की तो उस प्लांट के आस-पास के 7 गांवों से जमीन का अधिग्रहण कर उसने टाटा की मदद की।

इसके अलावा रिलायंस ने जामनगर में तेलशोधक कारखाने की स्थापना की तो 17 लोगों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया तो उनकी जमीनों का जब तक अधिग्रहण कर उनका मुआवजा बैंक में जमा करवा दिया। मोदी सरकार के पिछले 15 वर्ष बेशक उनके कहे अनुरूप गुजरात के विकास के रहे हैं। लेकिन यह दर-असल छोटी सम्पत्ति के अपहरण के रहे हैं।

बड़ी पूंजी ने लगातार छोटी सम्पत्ति का अपहरण किया है और नरेन्द्र मोदी देशी-विदेशी बड़ी पूंजी के संरक्षक बनकर उभरे हैं। चाहे वह रिलायंस, टाटा हो या फिर फोर्ड या मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां हों। इसलिए बड़ी पूंजी को आज मोदी की साम्प्रदायिक राजनीति से भी कोई परहेज नहीं रह गया है और मोदी अपने आकाओं को खुश रखकर प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण के बाद सम्पत्तिविहीन लोगों का रोजगार छिनने व छोटी सम्पत्ति का अपहरण होने से पैदा सर्वहारा, अर्धसर्वहारा मोदी जैसे शासकों के लिये भविष्य में खतरा ही बनेंगे।

- अनुपम, एटा